

प्रेषक,

डा० राकेश कुमार

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,

उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्,

मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक)

देहरादून

दिनांक ०९ दिसम्बर, 20०९

विषय:- मध्यान्ह भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर संविदा पर समन्वयक रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1200/म०भो०यो०-08/2009-10, दिनांक 13.08.2009 एवं संख्या-प्र०एवं स्था०/06/1731/ 2008-10/म०भो०यो० दिनांक 29.09.2008 के क्रम में, सम्बन्धित विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जनपद स्तर पर संविदा पर समन्वयक रखे जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय:-

(क) वेतन/मानदेय की व्यवस्था (समन्वयक का मानदेय तथा नियुक्ति का स्वरूप)-

समन्वयक के मानदेय पर होने वाला व्यय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद (एमएमई) के अन्तर्गत प्रबन्धन, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण एवं आन्तरिक अनुश्रवण मद से किया जायेगा तथा इनकी नियुक्तियाँ उपनल/पीआरडी अथवा अन्य सेवा दाता एजेंसी से अनुबन्ध के आधार पर की जायेगी। समन्वयक को तदनुसार अथवा उपनल द्वारा निर्धारित दरों, जो भी कम हो, के अनुसार मानदेय दिया जायेगा।

राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की सहमति से सेवा दाता एजेंसी द्वारा समय-समय पर परिवर्तित मानदेय की दरों से लागू होगी।

**(ख) प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद (एमएमई)—**

भारत सरकार द्वारा एमएमई मद के अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर खाद्यान्न की कीमत, कुकिंग कॉस्ट व झुलान भाड़ा की दरों को जोड़ते हुए उसके 1.8% की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में एमएमई के अन्तर्गत कुल धनराशि 105.12 लाख भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। एमएमई की प्रस्तावित धनराशि में से 50% धनराशि विद्यालय स्तर पर, 15% धनराशि शोध एवं मूल्यांकन तथा 35% धनराशि प्रबन्धन, पर्यवेक्षण एवं आन्तरिक अनुश्रवण पर व्यय की जाती है। उक्त 35% धनराशि अर्थात् ₹ 38.79 लाख में से समन्वयकों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

**(ग) शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता—**

पदनाम	आयु	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण योग्यता/अनुभव
समन्वयक	21-35 वर्ष	विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष	कम्प्यूटर में हिन्दी व अंग्रेजी टंकण सहित MS-Office में कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य है। किसी सरकारी/गैर सरकारी विभाग अथवा परियोजना में कार्य करने वाले को परीयता दी जाएगी।

निर्धारित आयु सीमा में राज्य सरकार के नियमान्तर्गत छूट का प्राविधान होगा।

**(घ) कार्य एवं दायित्व (समन्वयक के कार्य एवं दायित्व)—**

- मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर समस्त अभिलेखों का रख-रखाव करना।
- राज्य स्तर से प्राप्त समस्त पत्रों का अध्ययन कर जनपदीय अधिकारियों से विचार-विमर्श कर निस्तारण करना।
- मासिक तथा त्रैमासिक सूचना तैयार कर राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराना।



- जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से निरन्तर समन्वयन करना तथा वहाँ से खाद्यान्न उठान-वितरण की सूचना प्राप्त कर प्रेषित करना।
- जनपद स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना की मासिक बैठकों का आयोजन कराना तथा राज्य स्तरीय बैठकों में प्रतिभाग करना।
- मामकानुसार मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ से कुकिंग मूल्य व अन्य मदों में धनराशि की मांग कर सत्काल विद्यालयों का प्रेषित करवाना।
- सभी विद्यालयों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- विकासखण्ड स्तर की समस्त सूचनाओं का जनपद स्तर पर संकलन कर विश्लेषण करना।
- विद्यालय स्तर पर माहवार खाद्यान्न के कुकिंग मूल्य, मानदेय इत्यादि के उपभोग की स्थिति से राज्य के मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ को जानकारी प्रदान करना।

#### (ड) कार्मिकों का मूल्यांकन-

समन्वयक अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) के नियन्त्रणाधीन तथा दिशा-निर्देशन में मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित कार्य करेंगे। इनके कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन संबंधित जनपदों के अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) के द्वारा किया जायेगा तथा एक वर्ष के कार्यकाल के पश्चात् कार्मिक के पुनः संविदा विस्तार हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर उसके कार्यों की आख्या अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) द्वारा प्रस्तुत की जायेगी ताकि उसके संविदा विस्तार पर विचार किया जा सके-

- कार्मिक की कार्यालय में नियमित समय पर उपस्थिति।
- कार्य के प्रति लग्न व समयबद्धता।
- अधिकारी तथा अपने सहकर्मी के साथ व्यवहार।
- कार्मिक का चरित्र तथा सत्यनिष्ठा।
- कार्य सम्पादन में तीव्रता तथा कुशलता, आदि।

उपरोक्त मानकों पर खरा न उतरने की दशा में आगामी वर्ष में कार्मिक को पुनः संविदा पर रखे जाने पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

कार्मिकों के वेतन व भत्तों पर आने वाला समस्त व्ययभार भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे प्रबन्धन, अनुश्रवण व मूल्यांकन मद से किया जायेगा। इससे राज्य सरकार पर कोई व्ययभार नहीं आयेगा।

3. कृपया तदनुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए तत्काल मध्याह्न भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर 13 समन्वयकों को सविदा पर रखे जाने की कार्यवाही सम्पन्न करवायें।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-675(P)/वित्त अनुभाग-3/2009, दिनांक 18.12.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० राकेश कुमार)  
सचिव।

संख्या व दिनांक सदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. मार्व फाईल।

आज्ञा से,

(ओ०पी०तिवारी)  
उप सचिव।